

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्चाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 09 अप्रैल 2007

विषय:-मै0 डॉ0 सूद लैबोरेट्रीज प्रा0 लि0 को चिकित्सा (लैबोरेट्री) की स्थापना हेतु जनपद उधमसिंहनगर की तहसील गदरपुर के ग्राम महतोष में कुल 0.632 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0- 581/सात-स0भू0अ0/2007 दिनांक 30 अप्रैल, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 डॉ0 सूद लैबोरेट्रीज प्रा0 लि0 को चिकित्सा (लैबोरेट्री) की स्थापना हेतु उत्तरांचल(उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा- 154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत तहसील गदरपुर के ग्राम महतोष के खाता सं0-19 में खसरा नं0- 364 रकबा 0.632 है0 भूमि के खातेदार श्री विजय कुमार पुत्र श्री नन्दलाल निवासी हरियावाला तहसील जसपुर जिला उधमसिंहनगर के नाम वर्ग 1(क) संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख हैं, को चिकित्सा (लैबोरेट्री) की स्थापना हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)-2005 के अन्तर्गत GIDCR में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।

8- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- इकाई द्वारा प्रस्तावित फार्मास्यूटिकल उत्पाद थ्रस्ट सेक्टर के क्रियाकलापों के अन्तर्गत होने पर इकाई को उत्तराखण्ड में कहीं भी स्थापित होने पर भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज 2003 के अन्तर्गत देय सुविधा/छूट का लाभ अनुमन्य होगा। परन्तु इकाई को 31-03-2010 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ करना होगा।

.....(3)

- 10- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोगारों को 70 प्रतिशत से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
 - 11- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र फार्मास्यूटिकल से सम्बन्धित उत्पाद के क्रियाकलापों की स्थापना हेतु किया जायेगा।
 - 12- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पॉट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
 - 13- इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व ड्रग कण्ट्रोलर से ड्रग लाईसेन्स, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
 - 14- प्रस्तावित इकाई का निर्माण कार्य सीडा से ले-आउट स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - 15- प्रश्नगत इकाई की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
 - 16- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)

प्रमुख सचिव।

१

संख्या एवं तददिनांक।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

.....(4)

- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
- 4- श्री केवल किशन सूद पुत्र श्री रघुवीर सिंह सूद पत्नी श्री केवल किशन सूद निवासी II सी/218 नेहरू नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश व श्री संजीव कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामानन्द 232/17 ई न्यू कोर्ट गांव गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।